लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 433

जिसका उत्तर बुधवार, 27 नवंबर, 2024 को दिया जाएगा

आवश्यक वस्तुओं की कीमतें

433. श्री मुरसोली एस.:
श्री ईश्वरस्वामी के.

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आवश्यक खाद्य और घरेलू वस्तुओं की आसमान छूती कीमतों से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा मूल्य वृद्धि संकट और आम लोगों पर इसके प्रभाव को कम करने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कोई अतिरिक्त खाद्यान्न और आवश्यक वस्तुएं आवंटित की हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि के कारण गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों के मुद्दे और उनके समक्ष आने वाली समस्याओं को कम करने के लिए क्या समुचित कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्री बी. एल. वर्मा)

(क) से (घ): उपभोक्ता मामले विभाग, देश भर में राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा केंद्रीय सहायता से स्थापित 555 मूल्य निगरानी केंद्रों द्वारा प्रस्तुत चयनित आवश्यक खाद्य वस्तुओं के दैनिक खुदरा और थोक मूल्यों की निगरानी करता है। कीमतों और सांकेतिक मूल्य प्रवृत्तियों की दैनिक रिपोर्ट का उचित विश्लेषण किया जाता है, ताकि बफर से स्टॉक जारी करने, स्टॉकहोल्डिंग संस्थाओं द्वारा स्टॉक का खुलासा करने, स्टॉक सीमा लगाने, आयात शुल्क को युक्तिसंगत बनाने जैसे आयात कोटा में बदलाव, वस्तु के निर्यात पर प्रतिबंध आदि जैसे व्यापार नीतिगत साधनों में परिवर्तन पर उचित निर्णय लिए जा सकें।

खाद्य वस्तुओं की कीमतें अस्थिर होती हैं क्योंकि वे कई कारकों से प्रभावित होती हैं, जैसे उत्पादन में मौसमीपन, प्रतिकूल मौसम की स्थिति, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, जमाखोरी और कालाबाजारी से उत्पन्न कृत्रिम कमी, अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि आदि। कभी-कभी आपूर्ति श्रृंखला में मामूली व्यवधान या प्रतिकूल मौसम की स्थिति आदि के कारण फसल को नुकसान होने से कृषि-बागवानी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है। इसके विपरीत, थोक आवक और लॉजिस्टीक समस्याओं से बाजार में अधिकता की स्थिति उत्पन्न होने और परिणामस्वरूप कीमतों में गिरावट आने की संभावना होती है।

गरीबों के लिए खाद्यान्न की पहुंच, खरीद का सामर्थ्य और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने 1 जनवरी, 2024 से अगले पांच वर्षों की अवधि के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के लगभग 81.35 करोड़ लाभार्थियों को उनकी पात्रता के अनुसार (अर्थात प्रति एएवाई परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न और प्राथमिकता वाले परिवार के मामले में प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न) मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।

सरकार अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) द्वारा नियमित समीक्षा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन और उपलब्धता पर कड़ी नज़र रखती है। समिति नियमित आधार पर आवश्यक कृषि-बागवानी वस्तुओं की कीमतों और मूल्य प्रवृत्तियों की स्थिति की समीक्षा करती है और घरेलू उत्पादन में वृद्धि और आयात के माध्यम से उपलब्धता बढ़ाने के उपाय सुझाती है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (डीएएफडब्ल्यू) इन सभी बैठकों में एक प्रमुख हितधारक है और उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए उपाय करना जारी रखता है।

बाजार में कीमतों को नियंत्रित करने के लिए बाजार हस्तक्षेप के लिए दालों और प्याज के बफर स्टॉक को अंशाकित और लक्षित तरीके से बनाए रखा गया है। भारत दाल ब्रांड के तहत बफर स्टॉक से दालों के एक हिस्से को उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर खुदरा बिक्री के लिए दाल में परिवर्तित किया जाता है। इसी तरह, आटा और चावल को भारत ब्रांड के तहत खुदरा उपभोक्ताओं को रियायती कीमतों पर वितरित किया जाता है। बफर से प्याज को थोक बाजारों में उच्च मूल्य वाले उपभोक्ता केंद्रों और खुदरा दुकानों के माध्यम से अंशाकित और लक्षित तरीके से जारी किया जाता है। प्रमुख उपभोग केंद्रों में स्थिर खुदरा दुकानों और मोबाइल वैन के माध्यम से खुदरा उपभोक्ताओं के बीच प्याज 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से वितरित किया जाता है। इन उपायों से दाल, चावल, आटा और प्याज जैसी आवश्यक खाद्य वस्तुओं को आम उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराने और कीमतों को स्थिर करने में मदद मिली है।

****